IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

RESPONSE ON BEHALF OF

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi

Petitioner

Versus

State of Uttarakhand

Respondents

1. Background:

That the above noted O.A. was listed for hearing on 10.11.2022, wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

> *"4. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of Uttarakhand, (2) Principal Secretary, Urban Department, State of Uttarakhand (3) State PCB, (4) Commissioner, Municipal Corporation, Dehradun, and (5) District Magistrate, Dehradun, who stand impleaded as respondents No. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1,2, 4 and 5 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*
>
> *6. Reply/response on behalf of State PCB be filed within two months as directed above"*

2. Observations of the Joint Committee:

The Joint Committee recommended following actions in the report;

a. To Payjal Nigam: It is necessary to trap all the drains.

b. To Jal Sansthan: It is necessary to connect the sewer connection of all the settlements along the river to the sewer line.

c. To Nagar Nigam: It should be ensured that the management of urban solid waste is done regularly in all the settlements on the banks of the river.

3. Action taken by UKPCB:

In compliance of the aforesaid order of this Hon'ble Tribunal and observations in the Joint Committee Report, the following actions have been taken by Uttarakhand Pollution Control Board;

a. The Member Secretary, UKPCB issued a letter dated 28.01.2023 to the Managing Director, Uttarkhand Payjal Nigam, Dehradun requiring him to provide current status and details of the action taken by the Department with respect to the observations of the Joint Committee within one week. In this connection, copy of the letter dated 28.01.2023 is being marked and filed as **Annexure No.1** to this response.

b. Further, the Member Secretary, UKPCB issued a letter dated 28.01.2023 to the Chief General Manager, Uttarakhand Jal Sansthan, Dehradun requiring him to provide current status and details of the action taken by the Department with respect to the observations of the Joint Committee within one week. In this connection, copy of the letter dated 28.01.2023 is being marked and filed as **Annexure No. 2** to this response.

c. It is pertinent to mention that at present, no reply has been received from the Uttarkhand Payjal Nigam, Dehradun and Uttarakhand Jal Sansthan, Dehradun till date.

****

Annexure-1

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)
E-Mail:- msukpcb@yahoo.com

यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–586/2023/ 1128 दिनांक 28.01.2023

एन0जी0टी0 मैटर/अतिमहत्वपूर्ण

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
11–मोहनी रोड़, देहरादून।

विषयः– मा0 एन0जी0टी में योजित वाद सं0 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 के अनुक्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच कमेटी की जांच आख्या इस कार्यालय को 25.10.2022 को प्राप्त हुई है। जिसको मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 03.11.2022 को दाखिल की गई। जिसके उपरान्त मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पुनः दिनांक 10.11.2022 के पैरा 4 में निम्न आदेश दिये गये हैं:–

> "4. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of Uttarakhand, (2) Principal Secretary, Urban Department, State of Uttarakhand (3) State PCB, (4) Commissioner, Municipal Corporation, Dehradun, and (5) District Magistrate, Dehradun who stand impleaded as respondents No. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondent No. 1, 2, 4 and 5 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त जांच कमेटी की जांच आख्या के अनुसार आपके विभाग से निम्नलिखित बिन्दुओ पर कार्य किये जाना शेष है।

1. वर्तमान तक 135 नालियों को टैप करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं मात्र 10 नालियों के टैपिंक का कार्य अवशेष है। जिससे माह दिसम्बर 2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।
2. रिस्पना वेसिन की लगभग 76 प्रतिशत बस्तियों को सीवरेज नेटवर्क से आच्छादित किया जा चुका है एवं शेष क्षेत्र को भी लाभान्वित करने हेतु कार्यवाही गतिमान है।
3. वीर गब्बर सिंह कालोनी, किशनपुर काठ बंगला, ढाक पट्टी, काठ बंगला भाग–2, आर्यनगर वस्ती, करनपुर खास, वस्तियों में सीवर ट्रीटमेंट हेतु नमामि गंगे में पृथक से प्रेषित प्रस्ताव की प्रगति।

अतः इस सम्बन्ध में संयुक्त जाँच कमेटी की आख्या संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है उपरोक्त बिन्दुओ पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति से एक सप्ताह में अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया अवगत होने का कष्ट करें कि प्रकरण पर मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 17.02.2023 को पुनः सुनवाई नियत है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एस0 के0 पटनायक)
सदस्य सचिव।

Annexure - 2

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)
E-Mail:- msukpcb@yahoo.com

यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–586/2023/1127 दिनांक 28.01.2023

एन0जी0टी0 मैटर/अतिमहत्वपूर्ण

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक
उत्तराखण्ड जल संस्थान
बी–ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून।

विषयः– मा0 एन0जी0टी में योजित वाद सं0 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 के अनुक्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच कमेटी की जांच आख्या इस कार्यालय को 25.10.2022 को प्राप्त हुई है। जिसको मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 03.11.2022 को दाखिल की गई। जिसके उपरान्त मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पुनः दिनांक 10.11.2022 के पैरा 4 में निम्न आदेश दिये गये हैं:–

"4. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of Uttarakhand, (2) Principal Secretary, Urban Department, State of Uttarakhand (3) State PCB, (4) Commissioner, Municipal Corporation, Dehradun, and (5) District Magistrate, Dehradun who stand impleaded as respondents No. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondent No. 1, 2, 4 and 5 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त कमेटी की जांच आख्या के अनुसार रिस्पना नदी के किनारे अव्यवस्थित बस्तियों को सीवर लाइन से आच्छादित करने हेतु लगभग 22 किमी सीवेज लाइन विछाने का प्रस्ताव है जिसके विरूद्ध वर्तमान तक 19.5 किमी0 सीवर लाइन विछाकर बस्तिओं को सीवेज सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है जिसमें उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा सीवर संयोजन का कार्य गतिमान है।

अतः इस सम्बन्ध में संयुक्त जाँच कमेटी की आख्या संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है उपरोक्त बिन्दुओ पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति से एक सप्ताह में अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया अवगत होने का कष्ट करें कि प्रकरण पर मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 17.02.2023 को पुनः सुनवाई नियत है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एस0 के0 पटनायक)
सदस्य सचिव।